भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2858
गुरूवार, 14 मार्च, 2013

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान

2858. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के शीघ्र निर्माण और अंगीकरण में तेजी लाने हेतु नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (एनएमईएम) प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित/निधियां कितनी हैं;

(घ) क्या हाइब्रिड वाहनों के प्रयोग और परिवहन के अन्य सतत रूपों को प्रयोग में लाने हेतु अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क) और (ख): जी हां, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और अंगीकरण में तेजी लाने के लिए सामान्य रूपरेखा तैयार करने हेतु नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की शुरूआत की है । हितधारकों के साथ विस्तारपूर्वक परामर्श और गहन अध्ययन के आधार पर सरकार ने इस पहल को मिशन मोड दृष्टिकोण से शुरू करने का अनुमोदन किया है । इसमें विभिन्न स्कीमों को तैयार करने, नीति हस्तक्षेप तथा परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। विभिन्न कार्य समूहों और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिषद की सहयोगात्मक संरचना का उपयोग संबंधित हितधारकों की सभी चरणों में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा ।

(ग): इस प्रयोजनार्थ अभी तक कोई निधि आबंटित/अभिचिह्नित नहीं की गई है ।

(घ) और (ड.): अभी तक, हाइब्रिड वाहनों और परिवहन के अन्य रूपों के प्रयोग के लिए इस पहल के तहत अनुसंधान और विकास हेतु किसी समर्पित संस्थान की स्थापना नहीं की गई है ।